आकाशवाणी गोरखपुर
प्रादेशिक समाचार

दिनांक–24 जुलाई 2024 **7:20 AM**

पहले मुख्य समाचार।

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में अपना सातवां और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट किया पेश : नई कर व्यवस्था में तीन लाख रूपये तक की आय पर नहीं लगेगा कोई कर, वेतनभोगी कर्मचारियों को आयकर में होगी बचत।
- बजट में कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए एक लाख बावन हजार करोड रुपये का किया गया प्रावधान, चार करोड़ से अधिक युवाओं के लिए दो लाख करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री पैकेज की भी घोषणा।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा– समृद्धि की राह पर गांव, गरीब, किसान को ले जाने वाला है बजट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा– विकसित भारत–आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज है बजट
- नीट यूजी की परीक्षा दोबारा कराने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार : कहा– मौजूदा आंकड़े नीट पेपर के लीक होने के नहीं देते संकेत।

****

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने कल अपना सातवां और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट वर्ष 2024–25 लोकसभा में पेश किया। वित्तमंत्री ने नौकरीपेशा और मध्यम आय वर्ग के लिए करों की दर संरचना में संशोधन किया गया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत अब तीन लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। तीन से सात लाख रुपए तक की आय पर पांच प्रतिशत, सात लाख से दस लाख रुपए तक दस प्रतिशत, दस से बारह लाख रुपए तक पंद्रह प्रतिशत, बारह से पंद्राह लाख रुपए तक बीस प्रतिशत और पंद्रह लाख रुपए से अधिक आय पर तीस प्रतिशत तक कर लगाए जाने का प्रस्ताव है। इससे नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर में 17 हजार पांच सौ रुपए तक की बचत हो सकेगी।

इसके साथ ही केंद्रीय बजट में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी मानक कटौती को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 75 हजार रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15 हजार रुपए से बढ़ाकर 25 हजार रुपए करने का प्रस्ताव है। इससे नई कर व्यवस्था में लगभग चार करोड़ वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा।

वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास कराधान को सरल बनाने का है। हमने पिछले पाँच वर्षों में अनेक उपाय किए हैं, जिसमें कॉरपोरेट टैक्स और व्यक्तिगत आयकर के लिए छूट और कटौतियों के बिना सरलीकृत कर व्यवस्थाएं प्रारम्भ करना शामिल है। वित्तवर्ष 2022–23 में 58 प्रतिशत कॉरपोरेट टैक्स सरलीकृत कर व्यवस्था द्वारा जमा किया गया।

बजट में रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एम एस एम ई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री की पांच योजनाओं और पहल के पैकेज की घोषणा की गई है।

प्रधानमंत्री पैकेज के भाग के रूप में रोजगार संबंधित प्रोत्साहन के लिए तीन योजनाएं लागू की जाएंगी। रोजगार पाने वालों को नियुक्त करने में कर्मचारियों और नियोक्ताओं की सहायता के लिए सब्सिडी के रूप में एक महीने का वेतन दिया जाएगा। दूसरी योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तीसरी योजना नियोक्ताओं पर केन्द्रित होगी। वित्तमंत्री ने बताया कि कृषि और सबंधित क्षेत्रों के लिए एक लाख 52 हजार करोड रुपये का प्रावधान किया गया है।

बजट में विकास आवश्यकताओं के लिए विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए विदेशी कम्पनियों पर कॉरपोरेट कर की दर चालीस प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत की गई है।

वित्त मंत्री ने ग्रामीण बुनियादी ढांचा सहित समग्र ग्रामीण विकास के लिए दो लाख 66 हजार करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा की है। अगले दो वर्ष में पूरे देश में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी। इसमें प्रमाण–पत्र और ब्रांडिंग की व्यवस्था भी शामिल है। दस हजार आवश्यकता आधारित संसाधन केन्द्र स्थापित किये जाएंगे। वित्तमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण में सरकार एक करोड़ शहरी निर्धन और मध्यवर्गीय परिवारों की आवास जरूरतें पूरी करने के लिए दस लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

****

बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो संदेश में कहा कि इस बजट से आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि के राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले दस वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, ये बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। ये नौजवानों को अनगिनत नये अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि आम बजट विकसित भारत–आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज है।

आम बजट सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी विकासोन्मुख एक सौ चालीस करोड़ भारतवासियों की आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आम बजट दो हजार चौबीस पच्चीस आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है। इस आम बजट में अंतोदय की पावन भावना विकास की असीम संभावना है। इस आम बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए एक लाख बावन हजार करोड़ रुपए कृषि और सहायक सेक्टर के लिए महिला सशक्तिकरण के लिए तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। स्वाभाविक रूप से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आधी आबादी इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली है।

उधर, कांग्रेस ने केंद्रीय बजट 2024–25 की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें आम आदमी के लिए कुछ भी नही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि बजट केवल भाजपा के सहयोगी दलों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है।

वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए कहा कि यह बजट महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को हल करने में विफल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में किसानों के लिए कुछ भी ठोस नहीं है, जब तक किसानों के मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता और युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित नहीं हो जाता, तब तक लोगों को लाभ नहीं मिलेगा।

****

मेडिकल में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा–नीट को रद्द कर के नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है। शीर्ष कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नीट दोबारा नहीं होगी।

सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद आंकड़े नीट पेपर के सिस्टमैटिक लीक होने के संकेत नहीं देते हैं। ऐसे में इस साल के लिए नए सिरे से नीट यूजी परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देना गंभीर परिणामों से भरा होगा, जिसका खामियाजा इस परीक्षा में शामिल होने वाले 23 लाख से अधिक छात्रों को भुगतना पड़ेगा और प्रवेश कार्यक्रम में व्यवधान पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा दोबारा कराने से तो इंकार कर दिया है लेकिन नीट में पूछे गए एक सवाल के सही विकल्प पर आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए दोबारा रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। इससे 13 लाखं छात्रों की रैंकिंग पर असर पड़ेगा। नीट की परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी और नतीजे 4 जून को घोषित किए गए थे।

****

प्रदेश के आरओ–एआरओ पेपर लीक मामले में कौशांबी पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 23 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक बृजेश श्रीवास्तव ने कहा कि अब प्रशासन की मदद से गैंग द्वारा अर्जित संपत्ति को सरकारी कब्जे में लेने की तैयारी है। आरओ–एआरओ परीक्षा का प्रश्नपत्र 11 फरवरी 2024 को परीक्षा से पहले ही लीक हुआ था।

****

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में विभिन्न आपदाओं में हुई जनहानि एवं क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा देने में शिथिलता बरतने पर आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। इसमें पांच जिलों के एडीएम एफआर को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है, जबकि तीन एसडीएम से स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं, बाढ़ संबंधी कार्यों में लापरवाही पर कानपुर देहात के आपदा विशेषज्ञ को निलंबित कर दिया गया है। सीएम ने सभी अधिकारियों को दो दिनों में अपना स्पष्टीकरण सौंपने के निर्देश दिये हैं। उधर, बलिया के बांसडीह कोतवाली गेट के सामने रोहित पांडेय की हत्या के मामले में पुलिस ने 25–25 हजार के दो इनामी आरोपियों को गिरफ्तार कर के जेल भेज दिया है। जबकि मुख्य आरोपी रोहित यादव ने अपने एक साथी के साथ कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। वहीं प्रशासन ने मुख्य आरोपी के साथ दो सहयोगियों के घरों पर बुलडोजर चला दिया है। वहीं, बहराइच में युवती से छेड़छाड़ करने एवं माहौल बिगाड़ने वाले नौ अरोपियों को गुंडा एक्ट के तहत गिरफ्तार कर के पुलिस ने जेल भेज दिया है।

****